स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–11, कार्तिक–मार्गशीर्ष 2068, नवम्बर 2011

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा-4

ध्यातव्य है कि जुलाई 2010 में दिल्ली में पेट्रोल 43 रूपये प्रति लीटर बिकता था। इसी प्रकार डीजल और रसोई गैस भी अभी से बहुत सस्ती थी। हालांकि पैट्रोलियम पदार्थों का बढ़ना कोई नई बात नही है। नया यह है कि पहले ये कीमतें सरकारी नियंत्रण में थी लेकिन जून 2010 से ये बाजारी नियंत्रण में चली गई. . .पहले से मारी मुद्रा स्फीति की मार झेल रहा आदमी सरकार की इस नीति से बिल्कुल असहाय सा हो गया है।

अनुक्रम

आवरण लेख
अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन से त्रस्त आम आदमी
– स्वदेशी संवाद /4

खाद्य तंत्र
अब सेहत पर बढ़ता संकट
– देविन्दर शर्मा /7

अर्थव्यवस्था
आम आदमी का बढ़ता असंतोष
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /10

स्वास्थ्य
जरूरत है स्वास्थ्य चिकित्सा पर ध्यान देना
– अवधेश कुमार /13

जनसंख्या
सात अरब होने पर हौवा
– भारत डोगरा /16

पर्यावरण
बीस साल पुराना सवाल
– सुनीता नारायण /19

दृष्टिकोण :
पटरी पर कैसे लौटे भारतीय रेलवे
– डॉ. अश्विनी महाजन /22

सुरक्षा :
सुरक्षा पर खतरनाक सुझाव
– अरुण जेटली /24

सामयिकी :
अमरीका की दोहरी नीति
– ब्रह्म चेलानी /26

लेख : पर्यावरण की भारतीय संकल्पना
– रेणु पुराणिक /28

तालाब : अनपढ़, असभ्य और अप्रशिक्षित
– अनुपम मिश्र /31

विचार–विमर्श : मुनाफाखोरी ने बनाया अमरीका को कंगाल
– डॉ. रजनीश त्यागी /34

पाठकनामा/2, आंदोलन/36

पाठकनामा

एफ–1 बनाम महंगाई और गरीबी

बीते माह ग्रेटर नोएडा में फार्मूला वन रेस का आयोजन हुआ। साथ ही एफ–1 की रेस देखने के लिए तमाम नेता, क्रिकेटर और फिल्मी सितारे भी जमा हुए। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को बनाने में 20 अरब रुपए खर्च किए गए। इस बुद्ध इंटरनेशनल के सर्किट को जेपी समूह ने बनाया इसके लिए उन्होंने सरकार से कोई मदद भी नहीं ली। यह समाचार प्रत्येक चैनलों पर दिखाया गया और सरकार से टैक्स में छूट की मांग भी की गई। कितने अफसोस की बात है कि महंगाई और गरीबी पर विचार करने के लिए कोई भी पार्टी एक साथ एकत्रित नहीं होती परंतु इस रेस को देखने के लिए भारत के कई दिग्गज नेता, मशहूर फिल्मी हस्ती और क्रिकेटर खिलाड़ी शामिल थे। आज देश महंगाई और गरीबी से जूझ रहा है साथ ही जनता दिन–प्रति–दिन बढ़ती पेट्रोल कीमतों, बढ़ती खाद्य पदार्थों की कीमत से परेशान है, वही दूसरी तरफ हमारे उद्योग जगत दुनिया का महंगा खेल अपने देश में आयोजित करते है। फार्मूला वन रेस को करने में आज भी कई विकसित देश डरते है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा खर्चा होता है, वही हमारे उद्योगपति इस खेल को कराने में भी नहीं चूकते है। कितनी दुख की बात है कि इन्हें जहां सब भेद–भाव भुलाकर देश में बढ़ती महंगाई और गरीबी पर सहयोग करना चाहिए था। वही दूसरी तरफ इन लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए फार्मूला वन रेस का कार्यक्रम आयोजित कर दिया। अब तो केवल जनता को ही जागना होगा और समझना होगा की महंगाई की मार उन पर ही पड़ती है – "नेता और उद्योग जगत व्यर्थ की ही चिंता उनके सामने करते है।" जनता को समझना होगा कि कौन सही है और कौन गलत? **–राकेश पाण्डेय, गली नं. 9, करतार नगर, दिल्ली**

चाइनीज वस्तुओं का करे बहिष्कार

मैं स्वदेशी पत्रिका का नियमित पाठक हूँ और स्वदेशी विचार केवल कहने के लिए ही नहीं अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश भी करता हूँ। मैं समझता हूँ देशहित सबसे पहले है साथ ही यह बात सबको समझने चाहिए। अगर हम बाजार से कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो सबसे पहले अपने देश में बनी वस्तुओं को ही प्राथमिकता दें। इससे देश में कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बेरोजगारी भी काफी हद तक कम हो जाएगी। आज देश में चीनी वस्तुओं का बोलबोला है। मैं दीपावली के एक दिन पहले सदर बाजार गया तो देखकर दुख हुआ। ड्रैगन का कब्जा दिल्ली के लघु उद्योग पर बढ़ता ही जा रहा था। सभी दुकानों पर चाइनीज सामान बिक रहा था। दुकानदारों ने बताया कि हमारे देश में बना माल काफी महंगा बढ़ता है जबकि चीनी माल काफी सस्ता पड़ता है। उन्होंने इसके लिए सरकार को ही दोषी बताया। दुकानदार भी चीनी सामान से चिंतित है और उनके अनुसार इससे हमारा लघु उद्योग दम तोड़ रहा है। एक दुकानदार ने काफी महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने कहा कि पहले चीन केमिकल काफी सस्ता देता था। जिसके कारण भारत में केमिकल निर्माण की काफी इकाइयां बंद हो गई और अब अचानक उसने 100 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए तक कर दिया है। इससे हमें समझना चाहिए कि चीन हमें क्यों सस्ता माल भेजता है? वो पहले हमारे देश के उद्योगों को तबाह करेगा फिर हमसे मनचाहा दाम वसूलेगा। जल्द से जल्द हो सके हमें चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ेगा अन्यथा चीनी ड्रैगन हमारे कई उद्योगों को चौपट कर देगा। **– अमरेश कुमार, आया नगर, नई दिल्ली**

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल होकर और भ्रष्ट लोगों को बचाकर लोकतंत्र और देश की छवि खराब करने का काम किया है।

– लालकृष्ण आडवाणी

एफ–1 को बेवजह प्राथमिकता दी जा रही है। यह हमारी आर्थिक ताकत का भोंडा प्रदर्शन है। पता नहीं हम किस तरह की संस्कृति को प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं।

– मणिशंकर अय्यर

असमान विकास के लिए अमेरिका सबसे अधिक जिम्मेदार है। बड़े अफसोस की बात है कि भारत और चीन विकास के अमेरिकी मॉडल का अनुसरण किए जा रहे हैं।

– जयराम रमेश

संपादकीय

महंगाई की आड़ में कपटी सरकार का खेल

आखिर वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने भविष्यवाणी की है कि मंहगाई दिसम्बर तक काबू में आ जायेगी। हालांकि वित्तमंत्री की यह भविष्यवाणी साधारण ज्योतिष की भविष्यवाणी से अधिक नहीं है, इसकी आधी बात अनुमान पर आधारित होती है। वित्तमंत्री ने मंहगाई कम करने के अपने आगे–पीछे शायद यह आधार सामने रखा है कि इस बार का मानसून काफी अच्छा रहा है और उपज अच्छी मिल सकती है। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो अच्छी उपज के बावजूद खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि दर नीचे नहीं आ सकती। अनुमान है कि थोक सूचकांक मूल्य वृद्धि दर 9 फीसदी से नीचे नहीं आयेगी इस समय यह मूल्य वृद्धि दर 9.5 फीसदी के आसपास है। वित्तमंत्री पहली बार कुछ गंभीरता से मूल्य वृद्धि के बारे में दावे करते नजर आये हैं। नहीं तो अभी तक सभी मंत्री और कांग्रेस के नेता यही कहते रहे हैं कि वे कोई ज्योतिष नहीं हैं कि बता सकें कि महंगाई कब कम होगी। खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि के लिये सीधे तौर पर जिम्मेदार कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री शरद पवार ने तो बचकाने बयान के रिकार्ड तोड़ दिये। वित्तमंत्री के बयान से पहले उनका यह अभियान आया था कि वे अर्थशास्त्र नहीं जानते हैं, उन्हें यह मालूम नहीं कि मूल्य कैसे बढ़ता और कम होता है। खैर, महंगाई में कमी आयेगी यह खबर अपने–आप में सुखद है। लेकिन इसमें दुखद पहलू यह है कि महंगाई कम करने के लिये अर्थव्यवस्था के पहिए को रोका गया। इसमें मानसून से कहीं अधिक भूमि का रिजर्व बैंक ही है। मार्च 2010 के बाद रिजर्व बैंक ने 12 बार ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी की है जिसके कारण विकास दर को बताने वाली सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर 8 फीसदी से नीचे आ गयी है। रिजर्व बैंक ने लगातार अपनी मौद्रिक नीति के जरिये अर्थव्यवस्था से पैसे खींचे। बाजार में तरलता कम होती गयी। उद्योग धंधे के लिये बैंक लोन आदि दुरूह होते गये और एक तरह से मुर्दनी सी छा गयी। लगातार कठोर मौद्रिक नीति ने बाजार पर असर डाला और मुद्रा स्फीति की वृद्धि दर पर थोड़ी रोक लगी। अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होते–होते मुद्रा स्फीति की दर 8 फीसदी से नीचे आ जायेगी। लेकिन यह एक सवाल भी खड़ा होगा कि क्या सरकार महंगाई को रोकने के लिये जिस तरह की मौद्रिक नीति अपना रही है उससे देश का आर्थिक विकास प्रभावित नहीं होगा? वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने ही एक अलग बयान में इसका जबाव दे दिया। उन्होंने कहा– इस वित्तीय वर्ष में 8 फीसदी की विकास दर हासिल करना मुश्किल होगी। यानि विकास को दांव लगाकर महंगाई पर कब्जे की सरकार कोशिश कर रही है। हालांकि देश के पास यह अवसर था कि पूरी दुनिया में फिर छा रही मंदी को अपने लिये फायदेमंद सौदे में तब्दील करता। दुनियाभर के, खासकर पश्चिमी देशों के उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। पूरा यूरोप मंदी की चपेट में आ चुका है। अमरीका पहले ही त्राहि–त्राहि कर रहा है। ऐसे में भारत भी अगर घुटने के बल बैठ जाता है तो स्थिति और भयंकर हो सकती है। क्योंकि बड़े देशों के निवेशक भारत समेत कुछ खास स्थिर अर्थव्यवस्था में ही निवेश की संभावना देख रहे हैं। लेकिन सरकार अपनी ही उलझनों में उलझी हुई है। उसके लिये खुद को बचाये रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिये कारगर नीति या रणनीति बनाने में फिसड्डी साबित हो रही है। सरकार के इस निकम्मेपन के कारण केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। निजी क्षेत्र में व्यापार के प्रति विश्वास या भरोसा गिरता जा रहा है। हाल ही में एक अंग्रेजी पत्रिका ने देश के प्रमुख 12 शहरों के 500 से ज्यादा प्रमुख उद्योगपतियों और व्यापारियों से देश के व्यवसायिक माहौल के बारे में जब एक सर्वेक्षण किया तो पाया कि लोगों में जबरदस्त उदासीनता है। अधिकांश उद्योगपतियों या व्यापारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में माहौल और खराब होगा। लोगों ने ही अभी से ही औद्योगिक उत्पादन कम कर दिये हैं और अपने निवेश को रोक दिया है। लाभ की स्थिति बिल्कुल निम्नतम स्तर पर पहुंच गयी है। उद्योगपतियों ने लोगों को नई नौकरियां देना भी बंद कर दिया है। यहां तक कि बैंकों ने भी अपनी विस्तार योजना ठप कर दी है। शेयर बाजार में भी पिछले कुछ महीनों में 25–30 फीसदी गिरावट के कारण कई बड़ी कंपनियों के हालात खस्ता हो गये हैं।

आवरण कथा

अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन से त्रस्त आम आदमी

पिछले कुछ वर्षों से यूपीए सरकार के द्वारा जो आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही हैं, उससे महंगाई तो बढ़ी ही है साथ ही विकास की संभावनाएं भी उत्तरोत्तर कम हो रही हैं। आम आदमी केवल खाने–पीने की वस्तुओं की महंगाई से नहीं बल्कि पेट्रोल, डीजल और गैस की भयंकर रूप से बढ़ती कीमतों से भी त्रस्त हैं। एनडीए सरकार के समय में घटती ब्याज दरों के कारण जिन लोगों ने कम ईएमआई के आर्कषण में घर और अन्य साजो–समान खरीदे, अब बढ़ती हुई ईएमआई के कारण परेशान हैं।

2009 में आम चुनाव से पहले यूपीए–1 सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 9 रूपये की कमी थी, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, उसके कुछ ही समय बाद दो किश्तों में पेट्रोल का दाम उससे ज्यादा बढ़ा दिया गया। 2010 में पैट्रोल की कीमतें कई बार बढ़ाई गई। पहले से भारी मुद्रा स्फीति की मार झेल रहा आदमी सरकार की इस नीति से बिल्कुल असहाय सा हो गया है।

15 सितम्बर 2011 को पैट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत फिर से 3 रूपये बढ़ा दी और दिल्ली में पेट्रोल लगभग 67 रूपये प्रति लीटर हो गया। इससे दो माह पूर्व ही कंपनियों ने रसोई गैस पर 50 रूपये प्रति सिलेण्डर, डीजल पर 3 रूपये और कैरोसिन पर 2 रूपये प्रति

स्वदेशी संवाद

लीटर बढ़ोतरी की थी। ध्यातव्य है कि जुलाई 2010 में दिल्ली में पेट्रोल 43 रूपये प्रति लीटर बिकता था। इसी प्रकार डीजल और रसोई गैस भी अभी से बहुत सस्ती थी। हांलाकि पैट्रोलियम पदार्थों का बढ़ना कोई नई बात नही है। नया यह है कि पहले ये कीमतें सरकारी नियंत्रण में थी लेकिन जून 2010 से ये बाजारी नियंत्रण में चली गई।

16 सितम्बर 2011 को भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2010 से लगातार 12वीं बार रेपोरेट और रिवर्स रेपोरेट में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उसे क्रमशः 8.25 प्रतिशत और 7.25 प्रतिषत कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि यह कदम लगातार बढ़ती महंगाई के मद्देनजर उठाया गया है। रेपोरेट वह ब्याज दर होती है, जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। रिवर्स रेपोरेट वह ब्याज दर होती है, जिस पर बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मात्र 17 से भी कम महीनों में 12 बार ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी सीधे तौर पर संकुचनवादी मौद्रिक नीति मानी जा सकती है। सामान्यतौर पर माना जाता है कि महंगाई का प्रमुख कारण मांग में वृद्धि होता है। वस्तुओं की कम उपलब्धता और बढ़ती मांग कीमतों पर दबाव बनाती है, इसलिए रिजर्व बैंक परंपरागत तौर पर ब्याज दरों में वृद्धि कर कीमतों को शांत करने का प्रयास करता है। लेकिन विडंबना यह है कि इतने कम समय में ब्याज दरों में भारी वृद्धि के बावजूद कीमत वृद्धि थमने का नाम नहीं ले रही और अगस्त माह तक आते–आते पिछले वर्ष की तुलना में महंगाई 9.78 प्रतिशत तक बढ़ गई।

खाद्य पदार्थों में यह वृद्धि लगभग 10 से 13 प्रतिशत के बीच बनी हुई है। लेकिन रिजर्व बैंक की मृग–मिरीचिका का कोई अंत नहीं है।

नीची ब्याज दरों के कारण विकास को मिली गति

यदि पिछले 12 वर्षों का हिसाब देखें तो पाते हैं कि कृषि की विकास दर कम होने के बावजूद अन्य क्षेत्रों में आमदनियां

बढ़ी और अर्थव्यवस्था की सकल संवृद्धि दर 6.5 से 9 प्रतिशत के बीच रही। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस दशक के पहले 6–7 वर्षों तक कीमतों में वृद्धि को काफी हद तक काबू में रखा जा सका। कीमतों में अपेक्षित नियंत्रण के चलते ब्याज दरें घटने लगी।

हालांकि घटती ब्याज दरों ने एक ऐसे वर्ग, जो ब्याज की आय पर आधारित था, को प्रभावित तो किया, लेकिन घटती ब्याज दरों ने देश में घरों, कारों, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं इत्यादि की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि की। कम ब्याज दरों के चलते सरकार द्वारा अपने पूर्व में लिए गए ऋणों पर ब्याज अदायगी पर भी अनुकूल असर पड़ा। हाऊसिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में तेजी से विकास होना शुरू हुआ और देश दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया।

यानि कहा जा सकता है कि भारत की आर्थिक संवृद्धि की गाथा में ब्याज दरों के घटने की एक प्रमुख भूमिका रही है।

ब्याज दरों में वृद्धि का मध्यम वर्ग के लिए मतलब

आज बढ़ती आमदनियों के युग में मध्यम वर्ग, विशेषतौर पर मध्यम वर्गीय युवा अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की जुगत में रहता है। ऐसे में अच्छा और अपना घर, कार अथवा मोटर साईकिल और जीवन का अन्य साजो–समान खरीदने के लिए वह बैंकों से उधार लेता है और उसे किश्तों यानि ईएमआई से चुकाता है।

पश्चिमी देशों से आई इस पद्धति से जीवन स्तर तो बेहतर हुआ, लेकिन आम आदमी की देनदारियां भी बढ़ गई। यह देनदारियां सामान्यतः स्थिर ब्याज दर पर आधारित नहीं होती। बढ़ते ब्याज दर से ईएमआई भी बढ़ जाती है। ऐसे में मध्यम वर्ग की ईएमआई बढ़ते जाने से रोजमर्रा के लिए उसके पास आमदनी बहुत कम बचती है।

पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत और आदमी

सरकार का यह तर्क है कि तेल कंपनियों के बढ़ते घाटे के मद्देनजर पेट्रेलियम पदार्थों की कीमतों का बढ़ाना अवश्य है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग का मात्र एक पदार्थ नहीं है। यह यातायात, उद्योग आदि के लिए एक कच्चा माल भी है। जाहिर है कि किसी भी उद्योग के कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने पर उस उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ जाती है। यानि बसों और यातायात के अन्य साधनों के किराये तो बढ़ेंगे ही साथ ही साथ वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ने के कारण उनकी कीमतों में भी वृद्धि होगी।

पेट्रोलियम कंपनियों को घाटे का झूठ

पहले सरकार आम व्यक्ति की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम कीमतों को निर्धारित करती थी और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें वर्ष में एक या दो बार से ज्यादा नहीं बढ़ाई जाती थी। और कभी कभी तो कच्चे तेल की कीमतों में कमी के चले पेट्रोलियम कीमत को कम भी किया गया। सरकार कीमतों को स्थिर रखने के लिए बजट में भारी प्रावधान करते हुए पेट्रोलियम कंपनियों को कोई बहुत बड़ी सहायता भी नहीं दे रही थी। पेट्रोलियम कंपनियों को यह निर्देश था कि वे घाटा होने की स्थिति में 'ऑयल बांड' निर्गमित करके उससे अपने घाटे की भरपाई करें।

सब जानते है कि अंतराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार एक जैसी नहीं रहती, कभी कीमतें बढ़ती है तो कभी कीमतें बहुत कम हो जाती है। पिछले एक वर्ष में अंतराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 64 डॉलर प्रति बैरल से लेकर 90 डॉलर प्रति बैरल तक रिकॉर्ड की गई। यदि पिछले 2 वर्षों का हिसाब लें तो अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की न्यूनतम कीमत 34.57 डॉलर प्रति बैरल रिकॉर्ड की गई। इसलिए पेट्रोलियम कंपनियों को पुरानी व्यवस्था यानि कीमतों पर सरकारी नियंत्रण में भी कोई नुकसान नहीं होता था।

यदि इन कंपनियों का हिसाब–किताब देखें तो वर्ष 2008–09 में ओ.एन.जी.सी को 16041 करोड़ रूपये, 'गैल' को 2814 करोड़ रूपये, इंडियन ऑयल को 2570 करोड़ रूपये और ऑयल इंडिया को 2166 करोड़ रूपये का लाभ हुआ।

वर्ष 2009–10 में यह लाभ और ज्यादा बढ़ता हुआ क्रमशः 16745 करोड़ रूपये, 3139 करोड़ रूपये, 10321 करोड़ रूपये और 2611 करोड़ रूपये हो गया। इन दोनों वर्षों में पुरानी व्यवस्था लागू थी। इसके अलावा एक अन्य रोचक बात यह है कि 217 सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा जो 92593 करोड़ रूपये का लाभ हुआ, उसमें मात्र तेल कंपनियों द्वारा ही 32857 करोड़ रूपये का लाभ हुआ।

यानि कुल लाभ का 36 प्रतिशत मात्र पेट्रोलियम कंपनियों से ही प्राप्त हुआ। यानि पेट्रोलियम कंपनियों के नुकसान का तर्क सीधे तौर पर गलत सिद्ध होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर करों से केन्द्र और राज्य सरकारों को लगभग 2 लाख करोड़ रूपये का राजस्व भी प्राप्त होता है। ऐसे में यदि पेट्रोलियम पदार्थों के वितरण में थोड़ा बहुत नुकसान भी हो तो भी सरकारें अपने इस राजस्व में से उसकी भरपाई आसानी से कर सकती हैं और सामान्य जन को महंगाई के इस आक्रमण से बचा सकती हैं।

महंगी होती दवाईयां

देश की 1978 में घोषित दवा नीति के अनुसार विदेशी कंपनियों के कार्यकलापों पर कुछ अंकुश लगाये गये थे और भारतीय कंपनियों को वरीयता देने का प्रावधान भी उसमें शामिल था। 1979 के दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के अनुसार 347 दवाईयों पर कीमत नियंत्रण का प्रावधान